श्री महेन्द्र मोहन: मैं समाचार-पत्र उद्योग से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं एक भाषा के समाचार-पत्र से जुड़ा हुआ हूं। मैंने इसीलिए बांग्ला, आसामी, तेलगु की बात कही है। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि पर्यटन विभाग अपना खर्चा करता है, वह किस भाषा में कितना रुपया व्यय करता है? इसकी जानकारी सदन में अवश्य रखी जाए।

श्रीमती अम्बिका सोनी: सभापति महोदय, हालांकि यह सवाल इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है इसलिए मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि हमारी एक स्पेशल कमेटी है जो बराबर छानबीन और समीक्षा करती है। हमारा टॉरगेट वह ग्रुप है, जो देश में भ्रमण करना चाहता है और विदेश में जाना चाहता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कोई भी ऐसी भारत की भाषा नहीं है, जिसमें "अतुल्य भारत" की ऐड न प्रकाशित हुई हो। हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि हम देश के हर अखबार में यह ऐड दे सकें, क्योंकि हमारा बजट बहुत कम है। ...**(व्यवधान)**...

श्री महेन्द्र मोहन: किस भाषा में कितना व्यय किया गया, इसका विवरण आप सदन में रखिए।

श्री सभापति: आप जवाब सुन लीजिए।

श्रीमती अम्बिका सोनी: सर, हम लोगों ने अब पिछले कुछ सालों से यह भी प्रयास किया है कि अगर पिछले साल देश के इतने अखबारों को ऐड दिए गए, तो अगले साल हम उनमें कुछ रोटेशन कर सकें। लेकिन हमारा यह प्रयास रहता है कि देश की सभी भाषाओं में चाहे वह तेलगु हो, कन्नड़ हो, मलियालम हो, उर्दू हो, हिन्दी हो, पंजाबी हो, सब अखबारों में हमारे इश्तहार छपे हैं। कौन से अखबार हैं, इसके बारे में मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कमेटी है, जो इसकी हर साल समीक्षा करती है कि किन अखबारों को ऐड दी जाए। मुझे मालूम है कि 'Incredible India' के इश्तहार में कभी उनके साथ शाहरूख खान जुड़े हों या आमिर खान जुड़े हों या देश का आम आदमी जुड़ा हो, सब लोग चाहते हैं कि वह इश्तहार उनके अखबारों में छपे, हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में देश के हर अखबार में कुछ न कुछ दे सकें।

तेल कंपनियों के सामाजिक दायित्व

*102. **श्री शिवानन्द तिवारी** :††

डा. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व को ध्यान में रख कर देश की तेल कंपनियां अपने वार्षिक अर्जित लाभ का दो प्रतिशत सामजिक सुधार कार्य-कलापों पर व्यय करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा शुरू किए जाने वाले सामाजिक सुधार कार्यकलापों के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों द्वारा क्रमशः विगत वर्षों 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान व्यय की गई राशि और साथ ही वर्ष 2008-09 के दौरान दिसम्बर तक इस संबंध में व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

††सभा में यह प्रश्न श्री शिवानन्द तिवारी द्वारा पूछा गया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिन्शा जे. पटेल): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों पर पिछले वर्ष के अपने निवल लाभ का 0.75% से 1% तक खर्च करती रही हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के साथ हुई बैठक में यह संकल्प लिया गया था कि अगले वित्त वर्ष से हमारे सभी तेल पीएसयूज द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों पर पिछले वर्ष के निवल लाभ का कम से कम 2% खर्च किया जाएगा। तथापि सीएसआर क्रियाकलापों के लिए आबंटन पिछले वर्ष में आबंटन से कम नहीं होगा। इसके अलावा सीएसआर क्रियाकलापों के लिए आबंटन की गई कोई भी राशि जो खर्च न की गई हो, अगले वर्ष के आबंटनों में जोड़ी जाएगी। सभी तेल पीएसयूज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को सीएसआर स्कीमें क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त प्रत्यायोजित शक्तियों वाले समर्पित टीमें बनाने की सलाह दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष (दिसम्बर, 2008 तक) के दौरान प्रमुख तेल पीएसयूज द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों पर खर्च की गई धनराशियों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

(रुपए लाख में)

तेल पीएसयूज का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (दिसम्बर, 2008 तक)
आईओसीएल	2026.00	3253.00	6427.00	2571.00
ओएनजीसी	5421.00	8262.50	12401.00	5996.00
ओआईएल	1785.69	2378.74	2893.02	1273.33
एचपीसीएल	479.14	843.09	667.11	648.41
बीपीसीएल	737.00	812.00	738.00	1293.00
गेल	1428.61	1131.64	1544.18	709.32

Social responsibilities of oil companies

†*102 SHRI SHIVANAND TIWARI: ††

DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that keeping in view the corporate social responsibility, oil companies of the country have agreed to spend two per cent of their annually earned profit on social reform activities;

(b) if so, whether Government has prepared any roadmap for social reform activities to be undertaken by public sector oil companies;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the details of the amount spent by these companies during the years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 and the amount spent in the year 2008-09 till December, in this regard?

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shivanand Tiwari.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DINSHA J. PATEL): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (c) Oil Public Sector Undertakings (PSUs) have been spending 0.75% to 1% of their net profits of the previous year on Corporate Social Responsibility (CSR) activities. In a meeting with CMDs of Oil PSUs recently, it was resolved that with effect from next financial year, all Oil PSUs will spend at least 2% of the net profits of the previous year on CSR activities. The allocation for the CSR activities will, however, not be less than the allocation in the previous year. Further, any amount allotted for CSR activities but not spent will be added to the next year's allocations. CMDs of all Oil PSUs have been advised to form dedicated teams with sufficient delegated powers to implement the CSR schemes.

(d) Details of amount spent on CSR activities by major Oil PSUs during the last three years and the current year (till December, 2008) are indicated below:

(Rs. in lakhs)

Name of PSU	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (upto December 2008)
IOCL	2026.00	3253.00	6427.00	2571.00
ONGC	5421.00	8262.50	12401.00	5996.00
OIL	1785.69	2378.74	2893.02	1273.33
HPCL	479.14	843.09	667.11	648.41
BPCL	737.00	812.00	738.00	1293.00
GAIL	1428.61	1131.64	1544.18	709.32

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, मेरे सवाल के जवाब में उत्तर आया है कि Oil Public Sector Undertakings जितने हैं, उन लोगों के साथ सरकार से यह तय हुआ था कि साल में उनका जो नेट प्रॉफिट होगा, उसका दो परसेंट वह कारपोरेट सोशल रेस्पांसेबिलिटी को निभाने में खर्च करेंगे। आप देखिए कि 2008-09 का आंकडा है कि 2008-09 में पेट्रोलियम प्रॉडेक्ट का दाम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे ज्यादा था, लगभग 139-140 डालर प्रति बैरल दाम पहुंच गया था, उस साल भी जो इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, एचपीसीएल है, इन सबने प्रॉफिट कमाया है। सरकार जो यह कहती रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम महंगा हो जाने के कारण पेट्रोलियम कम्पनियों को घाटा लग रहा है...। यह बात इस जवाब से ही गलत प्रमाणित होती है कि सरकार देश की आंखों में धूल झोंकने का काम करती रही है।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री शिवानन्द तिवारी: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रोफिट का जो दो परसेंट खर्च करना है उसका एक परसेंट भी खर्चा नहीं किया। सरकार ने खुद एडमिट किया है कि 0.7 परसेंट से लेकर 1 परसेंट तक ही खर्चा किया है। एक तो सरकार देश में भ्रम पैदा कर रही है कि ऑयल सैक्टर की कम्पनियों को घाटा हो रहा है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि उनका दाम घटाने के बारे में क्या सोच रही है? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए, भाषण मत दीजिए। ...**(व्यवधान)**... वह अलग सवाल है। आप एक सवाल पूछिए, दूसरा नहीं।

श्री शिवानन्द तिवारी: दूसरे, हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने यह कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि अगले साल दो परसेंट खर्च हो, लेकिन कम से कम एक परसेंट से कम खर्चा न हो।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री शिवानन्द तिवारी: तो उसका क्या कारण है कि आप ऑयल सैक्टर की कम्पनियों से दो परसेंट खर्चा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं?

श्री सभापति: अगर आप इतना टाइम एक सप्लीमेंट्री पर लेंगे तो दूसरा सप्लीमेंट्री आपको नहीं मिलेगा।। would request the hon. Members to ask questions, not to make statements.

श्री मुरली देवरा: सर, सम्माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि आज कार्पोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटीज के प्रोग्राम में ऑयल कम्पनियां खर्चा कर रही हैं। वह खर्चा एक परसेंट से कम है, यह बात सही है। इस फरवरी में एक मीटिंग के अंदर यह तय किया गया कि ऑयल कम्पनियां अपने नेट प्रोफिट का कम से कम दो परसेंट उसमें लगाएं। मैं आपको फख के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में मिनिमम दो परसेंट लगाया जाएगा। जहां-जहां पर पुराने साल का खर्चा आगे नहीं बढ़ाया गया होगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करके लगा दिया जाएगा। लास्ट इयर PSUs ने 246 करोड़ इसमें लगाया है। मुझे पूरी आशा है कि जो वायदा हमने दो परसेंट का किया है, उसको आने वाले साल में CSR के प्रोग्राम में लगाएंगे।

श्री शिवानन्द तिवारी: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने ऑयल सैक्टर की कम्पनियों को जो छूट दी है कि पिछले वर्ष जो उन्होंने खर्च किया है, उससे कम खर्चा नहीं करेंगी। तो इस छूट के बाद आप कैसे उम्मीद करते हैं कि खर्च करने का जो दो परसेंट का टारगेट है, उसको यह कम्पनियां पूरा करेंगी?

श्री मुरली देवरा: इसमें कोई समस्या नहीं है, जिन्होंने जो टारगेट पूरा नहीं किया होगा वह बाकी बचेगा उन पैसों को कैरी फारवर्ड करके नेक्स्ट इयर यूज कर दिया जाएगा।

श्री शिवानन्द तिवारी: फिर उसके बाद भी कैरी ओवर होगा?

श्री सीताराम येचुरी: सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि कार्पोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी पर जो खर्चा हो रहा है, उसके मुकाबले में एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्चा हो रहा है? आखिर हर समय आपसे हमारी शिकायत यही है कि नेशनलाइज्ड ऑयल कम्पनियों को एडवर्टाइजमेंट करने की कोई गुंजाइश हम समझते नहीं है। इस पर जो पैसा खर्च होता है, उसकी जगह पर दाम घटाते तो जनता को फायदा होता। तो कार्पोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी के मुकाबले में कितना ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर रहे हैं?

श्री मुरली देवरा: एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च होता है, इसकी फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, वह मैं आपको दे दूंगा। दाम घटाने की बात अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छा था।। think you are satisfied now. You know how many times we have reduced the prices.

SHRI SITARAM YECHURY: You can do it more, Sir. You can do it more.

SHRI MURLI DEORA: Whatever we could do. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: You can do more. That is what I am saying.

MR. CHAIRMAN: That is a separate subject.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I would like to bring it to the notice of the hon. Minister that I have written four letters, and I have also taken it up in the meeting of the Committee on Welfare of SC and ST, requesting him, since the Oil Companies have agreed to assist the construction of Poor Girls Hostel in Guntur and Prakasam, to augment the funds of MPLADS, for which I have taken the initiative. Can the Minister categorically assure me to do so? Despite my several letters, they are saying that there was a crisis earlier. Now, they are also saying, "We are examining it!" The building is half complete. It will go a long way in helping the poor girls because the focus of this CSR scheme is to help the vulnerable sections of our society. It is a backward area. I have written so many letters, Sir. Collectors have also written saying that the building is half complete. The CSR scheme can go a long way in completing this Poor Girls Hostels in Guntur and Prakasm Headquarters, which I have taken up under MPLADS. I request the hon. Minister to categorically assure me that it will be done.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI JESUDASU SEELAM: The amount of expenditure is less than what he was expecting. Here is a proposal lying with ONGC, IOC and the other Oil Company, HPC. These three Companies can come forward to build one floor each. It is a six-floor hostel. Sir, girls from all the rural area come here.

MR. CHAIRMAN: You have asked the question. Let us hear the answer now.

SHRI MURLI DEORA: Sir, I would like to congratulate the hon. Member for putting before us such good suggestions for spending money on CSR. The Ministry, as well as, oil companies receive several such requests and I can assure you that we will find out as to what we can do about this.

MR. CHAIRMAN: Shri Sharad Yadav. ...*(Interruptions)*...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, the expenditure is not. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, please.

श्री शरद यादव: सभापित जी, यह जो दो फीसदी का सवाल है, मंत्री जी ने कहा है कि हम इसको पूरा करेंगे, यह ठीक है और स्वागत योग्य है, लेकिन देश की जितनी भी पेट्रोलियम कम्पनियां हैं, आप उन पर बोझ डाल रहे हैं। जो अन्य प्राइवेट कारपोरेट्स के लोग हैं, आपने उनकी सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी के लिए क्या कोई विचार किया है? यह सदन दोबारा नहीं आएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: यह सदन वापस आएगा।

श्री शरद यादव: समय कम है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लें।

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुरली देवरा जी जब दौरा करते हैं, इनसे पिछली बार भी कहा गया था कि जो प्राइवेट कारपोरेट्स के लोग हैं, रिलाइंस से लेकर प्राइवेट कम्पनियों ने जो पेट्रोल पम्प लगाए हैं, इनकी वजह से देश के सैकड़ों लोगों के खेत, खलिहान और सम्पत्ति डूब गई है। महोदय, आप से पिछली बार भी यह सवाल किया गया था कि आप ने इस क्षेत्र में क्या पहल की है? महोदय पूरे देश में इस

तरह का फ्रॉड करके - जो प्राइवेट कम्पनीज और कारपोरेट्स हैं, वे इससे निकल जाएंगे, तो इस देश में सरकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मामले में क्या पहल करने वाले हैं? जो दूसरे प्राइवेट कारपोरेट्स हैं, उनके ऊपर भी यह दो परसेंट लगाने का जो प्रोफिट का मामला है, इस बारे में आप क्या करेंगे?

श्री मुरली देवरा: सर, यह जो कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी की बात है, हम इसमें आने वाले सालों में मिनिमम दो परसेंट खर्चा करेंगे। जो पब्लिक सैक्टर की PSUs कम्पनियां हमारे साथ काम कर रही हैं और आपने जिनका नाम लिया है, मैं उनके लिए यह कह सकता हूं कि उनको डायरेक्ट सेंड करना हमारा काम नहीं है। जहां तक इसका सवाल है, हमने सुना है कि वे लोग भी CSR के अंदर कुछ कर हैं, लेकिन मुझे नही लगता कि कोई भी प्राइवेट सैक्टर की कम्पनी दो परसेंट तक करेगी। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: One question, please, तिवारी जी, आप बैठिए।

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैंने तो सीधा सवाल पूछा है कि देश में लोगों के जो खेत, खलिहान और सम्पत्ति डूब गई है और इन लोगों ने सब जगह पैट्रोल पम्प लगा दिए हैं, उनके बारे में सरकार क्या करेगी, आप क्या पहल करेंगे?

श्री मुरली देवरा: सर, यह इस सवाल से संबंधित नहीं है। यदि आप कहेंगे, तो मैं आपको इसके बारे में चिट्ठी लिखकर जवाब भिजवा दूंगा।

Tourist spots in the country

*103. SHRI SABIR ALI: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) the details of tourist spots in the country;

(b) the details of income accrued from them and expenditure incurred thereon during the last three years;

(c) the places which are being demanded to be developed as tourist spots; and

(d) what are the plans in this regard?

THE MINISTER OF TOURISM (SHRIMATI AMBIKA SONI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d) Identification and development of tourist spots is primarily undertaken by the State Governments/Union Territory Administrations. The Ministry of Tourism however, provides financial assistance to States/Union Territories for tourism projects on the basis of proposals received from them subject to availability of funds and *inter se* priority.

The Ministry of Tourism had also identified 22 destinations/ circuits based on their national importance, tourism footfalls and future potential, in consultation with the concerned State Governments for development of tourist infrastructure through mega projects. Projects for 20 destinations/circuits have been sanctioned. Out of these, Rs.37829.57 lakh have been sanctioned for 16 projects during the current financial year. Details are given in the Statement-I (*See* below).